

न्यायालय जिला कलेक्टर, सिरौही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

राजस्व अपील सं. 11/2020

अपीलांत

1. श्रीमती सीमा भाटिया पत्नि रमेश भाटिया, जाति घांची निवासी द्वारकाधीश मन्दिर के पास तहसील पिण्डवाडा, जिला सिरौही।
2. श्रीमती तारा पत्नि लालूराम, जाति घांची निवासी द्वारकाधीश मन्दिर के पास तहसील पिण्डवाडा, जिला सिरौही।

बनाम

रेस्पोंडेंट

1. राजस्थान सरकार जरिए उपतहसीलदार, भावरी।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पिण्डवाडा।
3. हल्का पटवारी भावरी।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-

1. श्री प्रमोद कुमार दवे अधिवक्ता अपीलांत।
2. पैरोकार सरकार।



निर्णय

दिनांक 22.09.2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि उप तहसीलदार भावरी द्वारा मौजा भावरी के खसरा संख्या 1172 पर अतिक्रमण करने से मुकदमा संख्या 163/2019 में पारित आदेश दिनांक 28.02.2020 से व्यथित होकर अपीलांत ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रेस्पोंडेन्ट्स के विरुद्ध प्रस्तुत की अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट्स को सम्मन जारी किया गया। रेस्पोंडेन्ट संख्या एक से तीन की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

दोनों पक्षों की बहस दिनांक 15.09.2020 को सुनी गई। अपीलांत के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि उप तहसीलदार, भावरी द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने में विधि एवं कानूनी तथ्यों की जांच किये बगैर निर्णय पारित किया गया है। अतः उक्त निर्णय में अंकित भूमि खसरा संख्या 1172 कुल रकबा 3750 वर्गफुट अपीलांत के पट्टेशु है। जो प्रायः पंचायत भावरी द्वारा श्री फताराम पुत्र श्री जोगाजी जोगी निवासी सिरौही तहसील पिण्डवाडा को पट्टा संख्या 1 बुक संख्या 111 दिनांक 09.04.2013 को जारी

जिला कलेक्टर, सिरौही

किया गया था जिसको अपीलान्त संख्या 1 ने जरिये विक्रय विलेख के 24.04.2013 के द्वारा रूपये 3 लाख 50 हजार में 1912.50 वर्गफुट भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया। एवं श्री मोहन पुत्र श्री वीराराम जोगी निवासी सरुपगंज को पट्टा संख्या 2 बुक संख्या 111 दिनांक 09.04.2013 को जारी किया गया था जिसको अपीलान्त संख्या 2 ने जरिये विक्रय विलेख के 24.04.2013 के द्वारा रूपये 3 लाख में 1912.50 वर्गफुट भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया।

अपीलान्त संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत भावरी से उक्त पट्टेशुदा भूमि पर निर्माण कार्य करने हेतु अनुमति मांगी गई जिस पर ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 10.09.2013 को प्रस्ताव संख्या 02/05 के द्वारा आज्ञा क्रमांक 333 दिनांक 12.09.2013 एवं अपीलान्त संख्या 2 द्वारा ग्राम पंचायत भावरी से उक्त पट्टेशुदा भूमि पर निर्माण कार्य करने हेतु अनुमति मांगी गई जिस पर ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 10.09.2013 को प्रस्ताव संख्या 02/04 के द्वारा आज्ञा क्रमांक 332 दिनांक 12.09.2013 अनुमति दी गई। रेस्पोजेन्ट द्वारा गैर कानूनी रूप से अपीलान्त के पट्टेशुदा भूमि में गलत जांच के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अपीलाधीन मुकदमा दर्ज कर अपीलान्त को अतिक्रमी घोषित करने में कानूनी भूल की है अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त करने हुए अपीलान्त को ग्राम पंचायत द्वारा दी गई आज्ञा के अनुसार भवन निर्माण करने की अनुमति यथावत बहाल रखी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे। इस संबंध में उनके द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 114 एवं सम्पत्ति अंतरण अधिनियम 1882 एवं रजिस्ट्रीकरण एवं अन्य संबंधित अधिनियम 2002 की धारा 51 एवं 55 प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि उक्त विधिक दृष्टांत विचारणीय प्रकरण में लागू होते हैं अतः अपीलान्त की अपील स्वीकार की जावे।

रेस्पोजेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा अपीलान्त अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि पटवारी हल्का भावरी द्वारा मौजा भावरी के खसरा नम्बर 1172 रकबा 3750 वर्गफीट किस्म गैर मुमकिन रास्ता पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर शुरुम निर्माण करने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक टीम का गठन किया जाकर मौके की भूमि का सीमांकन करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक भावरी, रोहिडा, वाटेरा एवं पटवारी हल्का भावरी को टीम शामिल किया जाकर जांच करवाने पर अपीलान्त का अतिक्रमण सही होना पाया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत कायम रखते हुए अपीलान्त की अपील खारिज की जावे।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया । अपीलान्त की ओर से प्रस्तुत अपील मीमो एवं रेस्पोजेन्ट की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभौति नियमों के परिपेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि विवादित भूमि मौजा भावरी के खसरा संख्या 1172 रकबा 3750 वर्गफुट किस्म गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है।

पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि खसरा संख्या 1172 किस्म गैर मुमकिन रास्ता की भूमि को कभी भी ग्राम पंचायत भावरी को आबादी विस्तारित आबंटित किया गया है। आज भी उक्त भूमि गैर मुमकिन आम रास्ता राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। ग्राम पंचायत को गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16

जिला कलेक्टर, सिरोही

के तहत गैर मुमकिन रास्ते की भूमि किसी भी व्यक्ति को आवंटन करने पर प्रतिबंध है।

विवादित भूमि राजस्व रेकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ते की भूमि दर्ज है जो कभी भी ग्राम पंचायत को आवंटन हुई हो ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि खसरा नम्बर 1172 रकबा 3750 वर्गफुट पर अपीलान्ट का अतिक्रमण ही माना जायेगा। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांत भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 114 एवं संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 एवं रजिस्ट्रीकरण एवं अन्य संबंधित अधिनियम 2002 की धारा 51 एवं 55 प्रकरण में लागू नहीं होते हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिपूर्ण होने से हस्तक्षेप करना न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत होगा अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत कायम रखा जाकर अपील खारिज की जाती है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।



(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही